गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 209
दि. 30.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

'देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी', छत्तीसगढ़ में डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित 60वीं डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक, डाटा-ड्रिवन मॉडल और एआइ आधारित समाधानों को अपनाने की सलाह दी, जिससे सुरक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

रायपुर, (जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित 60वीं डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस के दूसरे दिन अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक, डाटा-ड्रिवन मॉडल और एआइ आधारित समाधानों को अपनाने की सलाह दी, जिससे सुरक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

पीएम मोदी ने पुलिस बलों की सेवाओं, समर्पण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए डिजिटल टूल्स के उपयोग और राज्यों के बीच साझा रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने से न केवल सहयोग बढ़ता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत सुरक्षा ढांचा भी तैयार होता है।

प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष शनिवार को चार प्रमुख सत्र

आयोजित हुए। इनमें वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद-निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में एआइ व फोरेंसिक तकनीक के उपयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चचार्की गई।

विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने अपने-अपने प्रदेशों की सुरक्षा चुनौतियों और सुधारों पर प्रेजेंटेशन दिए।

अधिकारियों ने बताया कि शाम के सत्र में इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक तपन कुमार डेका ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए विजन 2047 का रोडमैप पेश किया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी अपने राज्यों की सुरक्षा स्थिति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

आज पुलिस पदक से सम्मानित होंगे अधिकारी

यह सम्मेलन उस समय आयोजित किया गया है, जब कुछ सप्ताह पहले लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के पीछे सक्रिय एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का राजफाश हुआ था। राज्यों के पुलिस अधिकारियों को इस फोरम से नई तकनीकों और नीतियों की जानकारी मिली है, जिन्हें वे अपने-अपने राज्यों में लागू कर सकेंगे। आधुनिक आपराधिक कानूनों का सही उपयोग पुलिसिंग को और प्रभावी बनाएगा। तीन दिवसीय कान्फ्रेंस का रविवार को अंतिम दिन है। पीएम पुलिस पदक प्रदान करेंगे।

दो दिन में इन विषयों पर मंथन

जन-आंदोलनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मजबूत और प्रभावी तंत्र की आवश्यकता। भारतीय भगोड़ों की वतन वापसी के लिए रोडमैप तैयार करना। अनुसंधान में फोरेंसिक तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना। सफल जांच सुनिश्चित करने और अपराध समाधान दर बढ़ाने की रणनीतियां।

ऑपरेशन सिंदूर नागरिक-सैन्य समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है : मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में बोले रक्षा मंत्री

प्रशासनिक मशीनरी ने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों के साथ मिलकर कार्य किया: रक्षा मंत्री

'युवा नागरिक सेवकों को राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना होगा; वीर सैनिकों की तरह, उन्हें भी कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा'

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने युवा नागरिक सेवकों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और वीर सैनिकों की तरह ही ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहने का आ'ान किया। रक्षामंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नागरिक-सैन्य समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां प्रशासनिक मशीनरी ने सशस्त्र बलों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार किया और जनता का विश्वास जीता। रक्षा मंत्री ने 29 नवंबर, 2025 को उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए।

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सशस्त्र बलों ने संतुलित और बिना किसी उकसावे के जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, लेकिन पड़ोसी देश के दुर्व्यवहार के कारण ही सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। उन्होंने सैनिकों की वीरता की सराहना की और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने

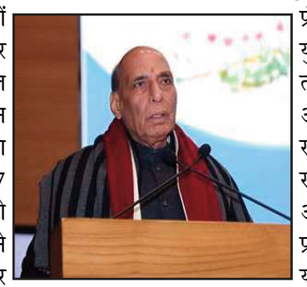

महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार किया और देश भर में मॉक ड्रिल का सफल संचालन सुनिश्चित किया। रक्षा मंत्री ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और 'सुधार, प्रदर्शन एवं परिवर्तन' के मंत्र का उल्लेख करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने में नागरिक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तब आर्थिक आकार के मामले में भारत 11वें स्थान पर था। पिछले 9-10 वर्षों में, हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। यहां तक कि मॉर्गन स्टेनली जैसी अत्यधिक प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म भी अब कहती है कि भारत अगले दो-तीन वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आप केवल आदर्शवादी संरक्षक नहीं, बल्कि लोगों के सेवक हैं। आप केवल प्रदाता ही नहीं, बल्कि सशक्तिकरण के सूत्रधार भी हैं। आपका चरित्र भ्रष्ट न हो। आपका आचरण सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण होना चाहिए। आपको एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहां सत्यनिष्ठा न तो कोई गुण हो और न ही अपवाद; बल्कि यह दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा हो। उन्होंने अधिकारियों से उत्तरदायी और सार्वजनिक जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री ने युवा नागरिक सेवकों से प्रौद्योगिकी-संचालित युग में नवोन्मेषी तरीके से कार्य करने और लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने का आ'ान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयकर विभाग की फेसलेस असेसमेंट योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी आज एक सक्षमकर्ता की भूमिका निभा रही है। रक्षा मंत्रालय की सम्पूर्ण पहल का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित स्वचालन प्रणाली है जो रक्षा खरीद और भुगतान का पारदर्शी तरीके से विश्लेषण करती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी एक माध्यम होनी चाहिए, साध्य नहीं। रक्षा मंत्री कहा ने अधिकारियों से कहा कि आपको जन-पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। कल्याण को बढ़ावा देने और समावेशिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी बल दिया कि नागरिक सेवकों के रूप में, प्रशिक्षुओं को प्रत्येक नागरिक के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी समाज के वंचित या कमजोर वर्गों के साथ संवाद करते हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि लोगों के संघर्ष न केवल उनके प्रयासों से, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। यही बात एक प्रशासक को वास्तव में जन-केंद्रित और करुणामय बनाती है।

रक्षा मंत्री ने सिविल सेवाओं में महिलाओं की निरंतर प्रगति को स्वीकार करते हुए कहा कि नवीनतम यूपीएससी परीक्षा में एक महिला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष पांच उम्मीदवारों में से तीन महिलाएं थीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक, कई महिलाएं कैबिनेट सचिवों के पदों तक पहुंचेंगी और भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करेंगी।

श्री राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन कोर्स को केवल एक प्रशिक्षण मॉड्यूल नहीं, बल्कि एक कुशल, सक्षम और संवेदनशील शासन प्रणाली के निर्माण की प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने एलबीएसएनएए की व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था की सराहना की, जो इसे एक संपूर्ण संस्थान बनाती है और देश की प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत बनाती है।

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की विरासत पर विचार व्यक्त करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके नाम पर स्थापित अकादमी साहस, सरलता और सत्यनिष्ठा की प्रतीक है। उन्होंने 1965 के युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व, हरित क्रांति में उनकी भूमिका और "जय जवान, जय किसान" के उनके संदेश को याद किया और अधिकारियों से उनके उदाहरण से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। यूपीएससी के 100वें वर्ष के अवसर पर, उन्होंने कहा कि यूपीएससी और एलबीएसएनएए के बीच साझेदारी ने प्रशासकों की कई पीढ़ियों को आकार दिया है और यह भारत के शासन ढांचे को मजबूत करती रहेगी।

महाराष्ट्र में आधार कार्ड को लेकर बदला नियम, कैंसिल होंगे ये लाखों बर्थ सर्टिफिकेट

महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि केवल आधार कार्ड दिखाकर किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम फजीर्वाड़ा रोकने के लिए उठाया है। इतना ही नहीं धोखाधड़ी वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को रद्द करने और मूल प्रतियों को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया है। बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेम्पल इकॉनमी के विजन के तहत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा

आध्यात्मिक पर्यटन और रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के योगी सरकार के अभियान की बरेली में रफ्तार तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य सेक्टर मद में शहर के दो प्रमुख मंदिर सीताराम झरोखा मंदिर और बड़ा बाग हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास को पंख लगेंगे।

(जीएनएस)।

बरेली। आध्यात्मिक पर्यटन और रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के योगी सरकार के अभियान की बरेली में रफ्तार तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य सेक्टर मद में शहर के दो प्रमुख मंदिर सीताराम झरोखा मंदिर और बड़ा बाग हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास को पंख लगेंगे। शासन ने प्रस्तावित योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और इसी महीने वित्तीय स्वीकृति के साथ बजट आवंटन की संभावना है। उपनिदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा भेजे गए

लगभग 6.78 करोड़ रुपये के दो बड़े एस्टीमेट को हरी झंडी मिलने के बाद नाथ नगरी के धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले नाथ कॉरिडोर के काम को भी नई गति मिलेगी। इसके बाद मंदिरों के सौंदर्यीकरण, संरचनात्मक विकास और पर्यटन सुविधाओं का काम तेजी से शुरू हो जाएगा।

सीताराम झरोखा मंदिर, 3.13 करोड़: शासन ने श्रीराम जानकी मंदिर (सीताराम मंदिर) के पर्यटन विकास के लिए भेजे गए 3.13 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। जल्द ही बजट आवंटन के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। यह मंदिर नाथ कॉरिडोर की महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ परिसर सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, आगंतुक सुविधाओं और धार्मिक पथ निर्माण का काम किया जाएगा।

बड़ा बाग हनुमान मंदिर, 3.65 करोड़ : हार्टमेन क्षेत्र में बड़ा बाग हनुमान मंदिर के लिए पर्यटन विभाग ने 3.65 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजा था, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के वार्षिक स्नेहमिलन में उपस्थित रहे

(जीएनएस)।

गांधीनगर,29 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (जीसीसीआई) के वार्षिक स्नेहमिलन अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी मिली है, जो अहमदाबाद मां विकास के नए बेंचमार्क सेट करेगी। इतना ही नहीं; इससे वर्ष 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों के आयोजन के द्वार भी खुले हैं।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशक्ति के फल गुजरात को सदा-सर्वदा मिलते रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हर क्षेत्र की क्षमता पहचान कर राज्य में व्यापार-उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात आज देश का ग्रोथ इंजन बना है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2035 में गुजरात@75 की चर्चा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित भारत@2047 के प्रधानमंत्री के सपने में गुजरात नए चिह्न अंकित करेगा ही।

राज्य की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में हर क्षेत्र के विकास की नींव डाली थी, जिसके कारण आज गुजरात में चिप से लेकर शिप तक का उत्पादन हो रहा है। सबको साथ रखकर राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर रखने के लिए प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल फॉर ग्लोबल' मंत्र का अनुकरण राज्य में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में जीसीसीआई सहित व्यापार-उद्योगों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में सभी से स्वदेशी का मंत्र अपना कर अपना योगदान देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के करकमलों से जीसीसीआई द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जीसीसीआई एन्युअल ट्रेड एक्सपो के द्वितीय संस्करण गेट (जीएटीई)-2026 के लोगो का अनावरण तथा पू. ज्ञानवत्सल स्वामी लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

चौथे नीलगिरि श्रेणी (प्रोजेक्ट 17ए) स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' को सौंपा गया

(जीएनएस)।

नीलगिरि श्रेणी (प्रोजेक्ट 17ए) का चौथा और मझगांव डॉक शिपबिल्डिंग लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित तीसरा जहाज, तारागिरि (यार्ड 12653), 28 नवंबर 2025 को एमडीएल, मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रोजेक्ट 17ए के फ्रिगेट बहुमुखी बहु-मिशन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

तारागिरी, पूर्व आईएनएस तारागिरी का एक नया रूप है, जो एक लिएंडर-श्रेणी का युद्धपोत था और 16 मई 1980 से 27 जून 2013 तक भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा रहा और जिसने राष्ट्र को 33 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान की। यह अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना के डिजाइन, स्टेल्थ, मारक क्षमता, स्वचालन और उत्तरजीविता में एक बड़ी छलांग को दशार्ता है, और युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी) द्वारा डिजाइन और युद्धपोत निरीक्षण दल (मुंबई) की देखरेख में निर्मित, पी17ए फ्रिगेट स्वदेशी जहाज डिजाइन, स्टेल्थ, उत्तरजीविता और युद्ध क्षमता में एक पीढ़ीगत छलांग को दशार्ते हैं। एकीकृत निर्माण के दर्शन से प्रेरित होकर, इस जहाज का निर्माण और वितरण निर्धारित समय-सीमा में किया गया।

पी17ए जहाजों में पी17 (शिवालिक) श्रेणी की तुलना में उन्नत हथियार और सेंसर सूट लगे हैं। इन जहाजों में संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्र लगे हैं, जिनमें एक डीजल इंजन और एक गैस टर्बाइन शामिल है जो प्रत्येक शाफ्ट पर एक नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर (सीपीपी) और अत्याधुनिक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) को चलाता है।

शक्तिशाली हथियार और सेंसर सूट में ब्रह्मोस एसएसएम, एमएफएसटीएआर और एमआरएसएएम कॉम्प्लेक्स, 76 मिमी एसआरजीएम, और 30 मिमी और 12.7 मिमी निकटरक्षा हथियार प्रणालियों का संयोजन, साथ ही पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए रॉकेट और टॉरपीडो शामिल हैं।

तारागिरी पिछले 11 महीनों में भारतीय नौसेना को सौंपा जाने वाला चौथा पी17ए जहाज है। पहले दो पी17ए जहाजों के निर्माण से प्राप्त अनुभव के आधार पर तारागिरी के निर्माण की अवधि को घटाकर 81 महीने कर दिया गया है, जबकि प्रथम श्रेणी (नीलगिरी) के निर्माण में 93 महीने लगे थे। प्रोजेक्ट 17ए के शेष तीन जहाज (एक एमडीएल में और दो जीआरएसई में) अगस्त 2026 तक क्रमिक रूप से वितरित किए जाने की योजना है।

सम्पादकीय

अफगानिस्तानियों से नाराज यूएस

पिछले वुछ दिनों से एक बार फिर अफगानिस्तान चचाओं में है। दो घटनाएं ऐसी हुईं हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को सुर्खियों में ला दिया है। पहली घटना अमेरिका की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में दिल दहलाने वाली घटना घटी। व्हाइट हाउस से वुछ ही दूरी पर बुधवार को दोपहर दो वेस्ट वजीनिया नेशनल गार्ड सदस्यों पर अचानक की गईं गोलीबारी ने पूरे शहर को झकझोर दिया। व्हाइट हाउस में लॉकडाउन लग गया है। दोनों सैनिकों की दुखद मौत हो गईं। वाशिंगटन की मेयर म्यूरियाल बाउजर ने इसे टारगेटिड शूटिंग बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावर को जानवर बताते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। यह गोलाबारी उस समय हुईं जब गार्ड के सदस्य एक मेट्रो स्टेशन के पास तैनात थे। हमलावर अचानक मोड़ से आया और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने लगा। वहीं आसपास मौजूद अन्य सैनिकों ने तुरंत भागकर मौके पर पहुंचे और हमलावर को काबू कर लिया। गोली चलाने वाले का नाम रहमानुल्लाह लकनवाल (29 वर्ष) बताया गया है। यह अफगानिस्तान का नागरिक है जो 2021 में अमेरिका आया था। कहा जा रहा है कि यह अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के लिए भी काम कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन सरकार के तहत अमेरिका में आए अफगानिस्तान के हर नागरिक को फिर से जांच करने का भी वादा किया।

ट्रंप ने फ्लोरिडा से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए हमलावर को चेतावनी देते हुए कहा कि वह बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। हमलावर ने हमला क्यों किया इसकी जानकारी अभी नहीं आई। पहली सुखी अफगानिस्तान की तब बनी जब व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलाने वाला एक अफगानी निकला। दूसरी सुर्खी तब बनी जब तीन दिन पहले अफगानिस्तान के एक मीडिया चैनल ने यह खबर चलाईं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गईं है। इस खबर के आते ही पाकिस्तान में आग लग गईं। बता दें कि इमरान खान पिछले दो साल से रावलपिंडी की मटियाला जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में बंद हैं। इमरान खान की सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इस बीच बेटे कासिम खान ने भी अपने पिता की सुरक्षा को लेकर एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। मेरे पिता 845 दिन से जेल में हैं। पिछले छह हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में एकांत में रखा गया है। यहां किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है। अदालत के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद उनकी बहनों को हर मुलाकात से वंचित किया गया है। न कोई फोन, न कोई मुलाकात और न ही उनके जीवित होने का कोई सुबूत। मैं और मेरे भाई हम दोनों का अपने पिता से कोई संपर्व नहीं हुआ है। कासिम ने लिखा है, यह पूरी तरह से ब्लैकआउट कोई सुरक्षा प्रोटोकाल नहीं है, यह उनकी स्थिति को छिपाने और हमारे परिवार को यह जानने से रोकने का एक सोचा-समझा प्रयास है। मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय एकांत वेंद्र के हर नतीजे के लिए पाकिस्तानी सरकार को नोटिस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह जवाबदेही ठहराया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान की मौत महज एक अफवाह हो और वह जिंदा हों।

भारत मोटापा और मेटाबोलिक डिसऑर्डर से निपटने के लिए सबूतों पर आधारित एकीकृत दृष्टिकोण को मजबूत कर रहा है: आयुष मंत्री

सीसीआरएएस-सीएआरआई बेंगलुरु आयुर्वेद और मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम के लिए एकीकृत तरीकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) अपने केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), बेंगलुरु के जरिए 1-2 दिसम्बर 2025 को ए.वी. रामा राव ऑडिटोरियम, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु में आयुर्वेद और मोटापे और मेटाबोलिक सिंड्रोम के लिए एकीकृत तरीकों पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन, सीसीआरएएस के 57वें स्थापना दिवस समारोहों के साथ हो रहा है।

भारतीय विज्ञान संस्थान और निमहन्स के साथ मिलकर आयोजित किए गए इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में मोटापे और मेटाबोलिक सिंड्रोम के बढ़ते बोझ को सबूतों पर आधारित आयुर्वेदिक और एकीकृत चिकित्सा तरीकों से कम करना है। यह यह वैज्ञानिक कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के अनुसंधान पर आधारित एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और दुनिया भर में स्वास्थ्य के नतीजों को बेहतर बनाने की कल्पना को दशार्ता है।

इस पहल की अहमियत बताते हुए, माननीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री प्रतापराव जाधव ने कहा, 'भारत एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल में अपने काम को मजबूत कर रहा है, और आयुर्वेद इस बदलाव का केन्द्र है। मोटापा और मेटाबोलिक डिसऑर्डर हमारे समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से हैं। यह सम्मेलन सबूतों पर आधारित तरीकों को मजबूत करने के हमारे इरादे को दिखाती है, जो आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस की सख्ती के साथ जोड़ते हैं। भारत सरकार दुनिया भर में स्वास्थ्य के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान, नवोन्मेष और बहुविषयक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।'

आयुष मंत्रालय के सचिव ने जोर देकर कहा, 'मेटाबोलिक बीमारियों के बढ़ते बोझ के लिए मिलकर काम करने वाले, विज्ञान पर आधारित समाधान की जरूरत है। आयुर्वेद एक समग्र, बचाव वाला और पर्सनलाइज्ड तरीका देता है, जो आज जैव चिकित्सा की प्रगति के साथ जुड़ने पर और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। यह सम्मेलन एकीकृत अनुसंधान में भारत की लीडरशिप बढ़ाने, क्लिनिकल सबूतों को मजबूत करने और भविष्य की स्वास्थ्य नीति बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है।'

सीसीआरएएस के डायरेक्टर जनरल, डॉ. रविनारायण आचार्य ने कॉन्फ्रेंस की वैज्ञानिक अहमियत पर जोर दिया और बताया, 'ऐसे समय में जब मेटाबोलिक बीमारियाँ खतरनाक दर से बढ़ रही हैं, आयुर्वेद की होलिस्टिक समझ असरदार और प्रैक्टिकल समाधान देती है। यह समेलन सबूतों पर आधारित बातचीत के जरिए पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को नवीनतम जैव चिकित्सा अनुसंधान से जोड़ने के लिए तैयार की गई है। इसके नतीजे एकीकृत देखभाल फ्रेमवर्क, ट्रांसलेशनल रिसर्च और ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में अहम योगदान देंगे।'

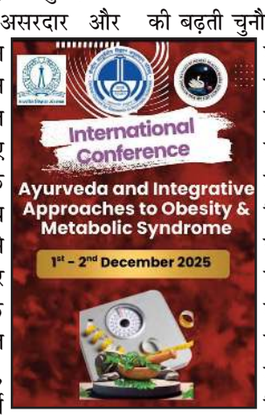

सेमिनार की यूनिट प्रमुख और आयोजन सचिव डॉ. सुखोलाचना भट्ट ने बताया कि "यह सम्मेलन आयुर्वेद और आधुनिक जैव चिकित्सा विज्ञान के जाने-माने विशेषज्ञों को मोटापे और मेटाबोलिक डिसऑर्डर की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए सबूतों पर आधारित एकीकृत तरीकों से एक साथ लाती है। उन्होंने आगे कहा कि सीसीआरएएस के रिसर्च जर्नल जेडीआरएएस का मोटापा और मेटाबोलिक डिसऑर्डर पर एक विशेष संस्करण, दस दूसरी किताबों के साथ, चल रही अनुसंधान की गहराई और वैज्ञानिक बातचीत और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।"

यह कॉन्फ्रेंस भारत और विदेश से आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा, जीव विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के जाने-माने विशेषज्ञों को एक साथ लाती है। शैक्षणिक कार्यक्रम में पूर्ण सत्र, समानांतर वैज्ञानिक सत्र और टाइप-2 डायबिटीज, मोटापा और डिस्लिपिडेमिया के ट्रांसलेशनल साइंस और एकीकृत प्रबंधन पर एक संगोष्ठी शामिल है। 2 दिसम्बर को टीसीएस स्मार्ट-एक्स हब, आईआईएससी में नैनोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर एक स्पेशल वर्कशॉप होगी। दोनों दिन समत्वम, पथशोध और सीएआरआई द्वारा एक हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप चलेगा। कॉन्फ्रेंस से पहले वर्चुअल साइंटिफिक बातचीत 25-27 नवम्बर 2025 तक हुई। कार्यक्रम के दौरान सीसीआरएएस के रिसर्च जर्नल जेडीआरएएस का मोटापा और मेटाबोलिक डिसऑर्डर पर एक विशेष संस्करण और 10 दूसरी किताबों का भी विमोचन होगा।

इसमें 700 से ज्यादा प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिसमें 267 मौखिक प्र॔तुति, 120 वर्चुअल पेपर प्रेजेंटेशन, 70 पोस्टर, और जाने-माने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अनुसंधानकताओं के 16 मुख्य भाषण और सम्मेलन के दौरान बातचीत होगी।

आयुर्वेद, मोटापा और दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ने के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीसीआरएएस एकीकृत अनुसंधान को आगे बढ़ाने, वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और सर्वांगीण और पहुंच योग्य स्वास्थ्य देखभाल की भारत की कल्पना के साथ साक्ष्य आधारित नवोन्मेष को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

कृषि क्षेत्र में हरित ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की कृषि मंत्रालय की वकालत के साथ ईआईएमए एग्रीमैच इंडिया 2025 का समापन

प्रदर्शनी में 20 हजार किसानों, 4 हजार से अधिक घरेलू डीलरों और वितरकों, 100 से अधिक विदेशी खरीदारों और 180 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से फिक्की और फेडरउनाकोमा ने कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया

कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और इटली के राजदूत कार्यक्रम में शामिल हुए

(जीएनएस)।

कृषि मशीनरी, उपकरण और कृषि तकनीक समाधान पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन 'ईआईएमए एग्रीमैच इंडिया 2025' का समापन आज भविष्य में हरित ईंधन आधारित कृषि मशीनरी पर फोकस करने के आ'ान के साथ हुआ। इसका आयोजन फिक्की और इतालवी कृषि उद्योग निकाय फेडरउनाकोमा ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से किया था।

नई दिल्ली में पूसा स्थित आईएआरआई मैदान में 27-29 नवंबर, 2025 को आयोजित इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के लगभग 20,000 किसानों, 4000 से ज्यादा घरेलू डीलरों और वितरकों, 180 से ज्यादा घरेलू और विदेशी कंपनियों, और अल्जीरिया, नेपाल, श्रीलंका, केन्या, ओमान, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम, ज़िम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के 100 से ज्यादा विदेशी खरीदारों ने हिस्सा लिया। इटली इस प्रदर्शनी का भागीदार देश था। नीदरलैंड, जापान, अमेरिका और पोलैंड ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

प्रदर्शनी में कृषि मशीनरी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जो हमारे देश के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा, इस आयोजन ने कृषि क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को पूरा करने वाले भारतीय और विदेशी दोनों ही प्रकार के उद्यमियों को बेहतरीन अवसर प्रदान किए।

उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव डॉ. देवेश चतुवेर्दी ने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वे हरित ईंधन (पर्यावरण में कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला ईंधन) आधारित मशीनीकरण को प्राथमिकता देकर भारतीय कृषि क्षेत्र के 2047 के विजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और कार्यभार को कम करने के लिए महिला-पुरूष निरपेक्ष कृषि उपकरण बनाकर महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करें।

डॉ. चतुवेदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "अगले 5-10 वर्षों में, हमें अपनी तकनीकों को हरित ईंधन पर आधारित कर देना चाहिए—चाहे वे विद्युत चालित ट्रैक्टर हों या ग्रामीण सीबीजी संयंत्रों के लिए उपलब्ध सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) पर चलने वाली मशीनें। इस बदलाव से किसानों के रखरखाव और संचालन लागत, दोनों में कमी आएगी। हमारी योजनाओं में हरित ईंधन आधारित तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं अपने इतालवी उद्योग साथियों से इस क्षेत्र में सहयोग करने का आग्रह करता हूं।"

विजन 2047 को प्राप्त करने में महिला किसानों को महत्वपूर्ण बताते हुए, सचिव ने उद्योग जगत का ध्यान महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाले बजट (जेंडर बजटिंग) की ओर आकर्षित किया और उनसे महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने का आ'ान किया।

डॉ. चतुवेदी ने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसलिए, ऐसे उपकरण डिजाइन किए जाने चाहिए जो महिलाओं को कठिन परिश्रम से राहत दिलाने का काम करें। उन्होंने कहा कि अक्सर नीति निमार्ता यह मान लेते हैं कि 'जेंडर बजटिंग' का मतलब केवल महिलाओं को मशीनरी का स्वामित्व देना है, लेकिन केवल इससे उनका कठिन परिश्रम कम नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा, "अधिकांश कठिन कृषि कार्य महिलाएं करती हैं, और इसलिए हमें महिलाओं के अधिक अनुकूल उपकरणों की जरूरत है, चाहे वे मैनुअल हों या मोटर चालित, जो वास्तव में उनके कार्यभार को कम करें।"

भारत में इटली के राजदूत श्री एंटोनियो बाटोर्ली ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में इतालवी दूतावास में शीघ्र ही एक कृषि अताशे (एक ऐसा अधिकारी जो कृषि क्षेत्र का विशेषज्ञ हो और दो देशों के बीच कृषि संबंधों को मजबूत करने के विभिन्न पक्षों का ध्यान रखे) की नियुक्ति की जाएगी।

प्रदर्शनी का अंतिम दिन दौरा करने वाले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अन्बलगन पी ने प्रदर्शनी एवं सम्मेलन की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी तथा घरेलू एवं विदेशी कम्पनियों, डीलरों, वितरकों की प्रमुख उपस्थिति इस आयोजन की सफलता को दशार्ती है।

ईआईएमए एग्रीमैच इंडिया की आयोजन समिति के अध्यक्ष और टैफे के बोर्ड निदेशक एवं समूह अध्यक्ष श्री टी.आर. केसवन ने कृषि को सेवा के रूप में बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया, क्योंकि किसानों को केवल कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल होने वाला सीडर खरीदना महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि सेवा के रूप में सीडर मददगार साबित हो सकता है। इसलिए, हमें सेवा के रूप में कृषि का एक नया क्षेत्र बनाने की जरूरत है। उद्योग ने कृषि मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है।

कृषि क्षेत्र में भारत-इटली सहयोग के भविष्य को लेकर उत्साहित फेडेरुनाकोमा की महानिदेशक सुश्री सिमोना रापस्टेला ने कहा कि भारत पर इतालवी व्यापार एजेंसी (आईसीई) की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र 2023 में कुल 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर का था और अगले दस वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2033 में 31.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत होगी।

फिक्की राष्ट्रीय कृषि समिति के सह-अध्यक्ष और कॉर्टेवा एग्रीसाइंस के दक्षिण एशिया अध्यक्ष श्री सुब्रतो गीद ने कहा, "भारत के लिए अपने खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने हेतु उत्पादकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। हमें किसानों को उच्च-गुणवत्ता वाले बीजों और कृषि उपज बढ़ाने के साधनों जैसे सही सामाग्रियों तक पहुंच प्रदान करके शुरूआत करनी होगी। हमें ऐसे आधुनिक तरीकों की आवश्यकता है जो श्रम को कम करें और दक्षता में सुधार करें। मशीनीकरण इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे प्रौद्योगिकी और प्रगतिशील सुधारों से मदद प्राप्त है। इन सभी कदमों के साथ मिलकर, एक ऐसी सुदृढ़ कृषि प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है जो किसानों और राष्ट्र दोनों के लिए लाभकारी हो।"

कार्यक्रम के दौरान फिक्की-पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट 'फार्म मैकेनाइजेशनः द पाथ टुआड्र्स फ्यूचर रेडी इंडिया' भी जारी की गई।

इतालवी व्यापार एजेंसी की उप व्यापार आयुक्त सुश्री सबरीना मंगियालावोरी ने कहा कि भारतीय किसान आधुनिक यांत्रिक समाधानों, जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, फसल संरक्षण और फसल के डंठल से अनाज या दानों को अलग करने की प्रक्रिया (थ्रेसिंग) को अपना रहे हैं।

इस आयोजन का 10वां संस्करण अगले वर्ष इटली में आयोजित किया जाएगा।

उत्तिरामेरुर की 1,000 साल पुरानी कहानी: पीएम मोदी ने किया जिक्र तो इतिहासकारों ने बताया पूरा मॉडल

उत्तिरामेरुर याद दिला रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन की उत्पत्ति प्राचीन है—आधुनिक चुनावी संस्थाओं के जन्म से बहुत पहले से ही यहां चुनाव संरचना, संहिता और प्रचलन रहा है.

तमिलनाडु के उत्तिरामेरुर शिलालेखों में प्राचीन लोकतंत्र की विस्तृत चुनावी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कुदावोलाई प्रणाली में ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाता था उम्मीदवारों की उम्र तीस से सत्तर वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें गांव में जमीन का मालिक होना आवश्यक था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के प्रसिद्ध उत्तिरामेरुर शिलालेखों का उल्लेख किया तो लोगों में उस व्यवस्था को जानने की रुचि जागृत हुई है. कई इतिहासकार और विद्वान इसे दुनिया के सबसे प्राचीन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के सबसे विस्तृत मॉडलों में से एक मानते हैं. उनकी टिप्पणियों ने चोल-युग की कुदावोलाई सिस्टम पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जो एक हजार साल से भी पहले प्रचलित एक चुनावी प्रक्रिया थी, जिसमें गांव के नेताओं का चयन एक विस्तृत चुनाव प्रणाली के माध्यम से किया जाता था.

इतिहासकार क्या कहते हैं

कांचीपुरम के पास उत्तिरामेरुर में प्राचीन वैकुंड पेरुमल मंदिर की दीवारों पर अंकित ये शिलालेख स्थानीय शासन के एक उच्च संरचित ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं. इतिहासकार डॉ. नंदिता कृष्णा ने एनडीटीवी से बात करते हुए इन शिलालेखों को एक

प्राचीन चुनाव आयोग की पुस्तिका की तरह बताया, जिसमें प्रक्रियाओं, पात्रता नियमों, अयोग्यता मानदंडों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है.इस प्रणाली का मूल कुदावोलाई पद्धति थी. ताड़ के पत्तों पर लिखे उम्मीदवारों के नाम एक बर्तन में रखे जाते थे और एक बच्चे को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्ची निकालने को कहा जाता था. तमिल विद्वान और तमिल के सहायक प्रोफेसर डॉ. बालाजी कहते हैं, "नेताओं का चुनाव पारदर्शी तरीके से और अक्सर संयोग से होता था, लेकिन केवल सख्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद ही." उम्मीदवारों की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गांव में जमीन का मालिक होना चाहिए था और सटीक हिसाब-किताब रखने वाला होना चाहिए था. जो लोग हिसाब-किताब जमा नहीं कर पाते थे, उन्हें और उनके परिवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता था.चोल राजा विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे, स्थानीय शासन इन निर्वाचित ग्राम निकायों द्वारा संचालित होता था, जो राजस्व, सार्वजनिक कार्यों और सामुदायिक मामलों का प्रबंधन करते थे. डॉ. कृष्णा जोर देते हैं, "यह विकेंद्रीकरण का एक मजबूत मॉडल था. भारत लोकतंत्र की जननी है. अंग्रेज भी इसे अपनाते थे. हमारे पास जो था, वह कहीं ज्यादा पुराना और गहराई से जड़ जमाए हुए था."दोनों विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि जमीन के मालिकाना हक पर जोर देने का उद्देश्य धनी लोगों को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि निर्णय लेने वाले लोग समुदाय के ज़िम्मेदार हितधारक हों. निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे गांव के संसाधनों की रक्षा करें, निष्पक्ष रूप से कर वसूलें और रिकॉर्ड बनाए रखें—ऐसा न करने पर कठोर दंड का प्रावधान था.जैसे-जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से चचाएं शुरू हो रही हैं, उत्तिरामेरुर याद दिला रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन की उत्पत्ति प्राचीन है—आधुनिक चुनावी संस्थाओं के जन्म से बहुत पहले से ही यहां चुनाव संरचना, संहिता और प्रचलन रहा है.

भारत निर्वाचन आयोग ने ईसीआईनेट डिजिटल मंच को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) सभी नागरिकों से ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड करने और ऐप पर 'सुझाव सबमिट करें' टैब का उपयोग करके ऐप को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देने का आ'ान किया है। यह 27 नवंबर, 2025 से 27 दिसंबर, 2025 के बीच किया जा सकता है।

ईसीआईनेट ऐप के परीक्षण संस्करण का उपयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हाल ही में हुए उपचुनावों के दौरान किया गया था। इस नए मंच ने बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत के रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्ति के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित करना संभव बनाया, जबकि पहले इसमें कई हफ़्ते या महीने लग जाते थे। बिहार चुनावों से प्राप्त जानकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को इस मंच की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है।

उपयोगकताओं के सुझावों की जांच की जाएगी और मंच को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए इसमें और सुधार किया जाएगा। ईसीआईनेट मंच का आधिकारिक लॉन्च जनवरी 2026 में निर्धारित है।

मतदाताओं की सुविधा में सुधार और तकनीक के इस्तेमाल से चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, ईसीआईनेट, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर शुरू की गई आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है । ईसीआईनेट ऐप के विकास पर काम 4 मई, 2025 को इसकी घोषणा के बाद शुरू हुआ।

ईसीआईनेट ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत ऐप है जो पहले से मौजूद 40 अलग-अलग चुनाव-संबंधी एप्लिकेशन/वेबसाइटों, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीवीआईजीआईएल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट ऐप), और अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) ऐप को एक ही इंटरफेस में एकीकृत करता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

भारत को आईएमओ काउंसिल में दोबारा चुने जाने के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले, वैश्विक समुद्री भूमिका मजबूत हुई

(जीएनएस)।

भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (आईएमओ) की काउंसिल में कैटेगरी बी में दोबारा चुना गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले 10 देश शामिल हैं। लंदन में 34वीं आईएमओ असेंबली में 28 नवंबर को चुनाव में भारत को इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसमें 169 वैलिड बैलेट में से 154 वोट थे।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने इस परिणाम को भारत के बढ़ते ग्लोबल मैरीटाइम असर का बड़ा समर्थन बताया। श्री सबार्नंद सोनोवाल ने कहा, 'आईएमओ में भारत की सफलता हमारे डायनैमिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के मैरीटाइम विजन का सबूत है।'

सबार्नंद सोनोवाल ने कहा, 'यह भारत के मैरीटाइम सेक्टर और हमारे देश के लिए गर्व का पल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन॔द्र मोदी जी के विजनरी और क्रांतिकारी नेतृत्व में, भारत एक बार फिर 2026-27 के टर्म के लिए आईएमओ काउंसिल में कैटेगरी बी में सबसे ज्यादा वोटों के साथ चुना गया है।' उन्होंने कहा, 'वैश्विक समुदाय से मिला यह शानदार जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के एक सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट और ग्रीन मैरीटाइम डोमेन बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता का एक मजबूत सबूत है। उनकी लीडरशिप ने भारत को ग्लोबल मैरीटाइम प्रोग्रेस में सबसे आगे रखा है और देश को इंटरनेशनल शिपिंग के भविष्य को बनाने में भरोसेमंद आवाज के तौर पर खड़ा किया है।'

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारतीय रेल एवं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के योगदान को महत्वपूर्ण बताया

(जीएनएस)।

माननीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज वडोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांफ्रेंस हॉल में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं वडोदरा मंडल के अधिकारिओं को सम्बोधित किया। श्री रवनीत सिंह ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की टीम एवं वडोदरा मंडल के अधिकारिओं से माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान, समर्पण और प्रतिबद्धता का आवाहन किया। उन्होंने वडोदरा मंडल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे बेस्ट डिवीजन बताया।

इस बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी ने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को प्रेजेंटेशन के माध्यम से गतिशक्ति विश्वविद्यालय की प्रगति और अचीवमेंट की जानकारी दी। प्रोफेसर चौधरी ने माननीय राज्य मंत्री को बताया कि परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), 2022 में संसद के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन कार्यरत, यह

विश्वविद्यालय रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानन, समुद्री, नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करता है। विश्वविद्यालय के चांसलर श्री अश्विनी वैष्णव (केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) हैं।

प्रोफेसर चौधरी ने आगे बताया कि हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सफ्रान ने विमानन और एमआरओ क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री रेडी पेशेवरों को तैयार करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। इस टडव के माध्यम से, जीएसवी ने अपने विमानन इंजीनियरिंग कार्यक्रम में विशेष लीप इंजन पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक एयरोइंजन प्रौद्योगिकियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि एयरबस और ऋश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए जॉइंट स्टडी करेंगे।

वडोदरा मंडल के रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को प्रेजेंटेशन के माध्यम से वडोदरा मंडल की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री भडके ने पैसेंजर रिवेन्यू , टिकट चेकिंग आदि में मंडल द्वारा अर्जित गए नए कीर्तिमान, मंडल में लोडिंग के नए ट्रैफिक, गैर किराया राजस्व के जरिये यात्री सुविधाओं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सामाजिक संघटनों एवं गैर सरकारी संघटनों द्वारा उपलब्ध कराई गयी यात्री सुविधाओं आदि की जानकारी दी।

श्री भडके ने दिवाली और छठ पर यात्री सुविधाओं के लिया मंडल द्वारा किये गए क्राउड मैनेजमेंट एवं ट-वळर जैसे अन्य विशेष प्रयासों तथा जनप्रतिनिधियों के मांग पर मंडल द्वारा शुरू की गयी नयी ट्रेनों एवं विभिन्न स्टेशनों के अतिरिक्त स्टॉपेज की भी जानकारी दी। उन्होंने माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मंडल के स्टेशनों पर चल रहे कार्यों एवं मंडल पर चल रही विकास परियोजनाओं से भी अवगत कराया।

इस बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर श्री मनोज चौधरी सहित संकाय सदस्यों, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई; नई रेल सेवा 'स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस' नाम से संचालित की जाएगी

नई ट्रेन सेवा जैसलमेर और राजस्थान के प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़कर यात्रा को बदलने के लिए तैयार है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास होगा।

राजस्थान में लगभग 4,000 करोड़ रुपये के निवेश से 85 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है: अश्विनी वैष्णव

(जीएनएस)।

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जैसलमेर स्टेशन से नई जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) रेल सेवा की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

श्री वैष्णव ने जनभावना को देखते हुए घोषणा की कि जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) एक्सप्रेस का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा जाएगा।

जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) जैसलमेर एक्सप्रेस के शुरू होने से राष्ट्रीय राजधानी और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रामदेवरा, जोधपुर, मकराना, जयपुर और अलवर जैसे शहर अब राष्ट्रीय राजधानी से अधिक आसानी और सुविधा से जुड़ जाएँगे।

यह नई सेवा उन्नत चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करेगी, प्रमुख पर्यटन स्थलों से संपर्क में सुधार लाएगी और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। एक विश्वसनीय और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करके यह ट्रेन निवासियों, पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायों सभी को समान

रूप से लाभान्वित करेगी और क्षेत्रीय गतिशीलता और विकास को मजबूत करेगी।

श्री वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय रेल तेजी से प्रगति कर रही है और प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय रेल अपनी विकास यात्रा को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में रेलवे विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और लगभग 55,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार के अंतर्गत अनूपगढ़ से खाजूवाला, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और भाभर तक एक नई लाइन का प्रस्ताव विभिन्न चरणों में है। इन लाइनों के निर्माण से न केवल आम जनता को लाभ होगा बल्कि सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक सहायता में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

श्री वैष्णव ने बताया कि 2014 से पहले राजस्थान के लिए वार्षिक बजट आवंटन केवल लगभग 680 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ रुपये हो गया है। पोकरण स्टेशन पर रेल सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा कि रामदेवरा-पोकरण वाया भैरव गुफा और कैलाश टेकरी नई रेल लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद इस स्टेशन पर सभी ट्रेनें रुकेंगी। उन्होंने अधिकारियों को इस लाइन का काम त्वरित गति से करने के निर्देश भी दिए।

श्री वैष्णव ने जैसलमेर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को कोचिंग डिपो के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जैसलमेर से और अधिक रेलगाड़ियाँ संचालित की जा सकें।

श्री वैष्णव ने जैसलमेर स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में कहा कि इसका कायाकल्प 140 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगभग 4,000 करोड़ रुपये के निवेश से 85 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में रेलवे के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए, छह जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें और एक जोड़ी अमृत भारत ट्रेन सहित अन्य सेवाएँ संचालित की जा रही हैं और पिछले छह महीनों में इस ट्रेन सहित आठ नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर के बीच ट्रैक नवीनीकरण कार्य को प्राथमिकता से करने के भी निर्देश दिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम के दौरान श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में सांसद श्री उम्मेदा राम बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और विधायक श्री छोटू सिंह ने भी अपने संबोधन में नई रेल सेवा और रेलवे विकास कार्यों के लिए श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

शरदकालीन सत्र 2025 - प्रशिक्षण पूर्णता परेड

(जीएनएस)।

29 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए), एझिमाला में एक भव्य प्रशिक्षण पूर्णता परेड (पीओपी) आयोजित की गई । कुल 232 प्रशिक्षुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण की समाप्ति का संकेत देते हुए उत्तीर्णता प्राप्त की, जिसमें 109वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के मिडशिपमैन , 39वें नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (विस्तारित) , 40वें नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (विस्तारित) , 41वें नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (नियमित और तटरक्षक) और 42वें नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (मित्र विदेशी देश) के कैडेट शामिल थे। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके समूह में सात मित्र विदेशी देशों (बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, मालदीव, म्यांमार, मोजाम्बिक, सेशेल्स) के 18 कैडेट शामिल थे , जो अकादमी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को दशार्ता है।

परेड का निरीक्षण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने किया । उन्होंने इस औपचारिक उपलब्धि के दौरान मिडशिपमैन और कैडेट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। निरीक्षण अधिकारी के साथ उनकी पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा चौहान भी मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, आईएनए के कमांडेंट वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और

विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए : -

(क) भारतीय नौसेना अकादमी बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिडशिपमैन विशेष कुमार को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया - जो आईएनए के समावेशी और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को रेखांकित करता है।

(ख) नौसेनाध्यक्ष रजत पदक मिडशिपमैन शौर्य आदित्य प्रजापति को प्रदान किया गया। कमांडेंट चैंपियन स्क्वाड्रन बैनर अचीवर स्क्वाड्रन को शैक्षणिक, सेवा विषयों, आउटडोर प्रशिक्षण, ड्रिल, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया।

(ग) मिडशिपमैन सिद्धांत जाखड़ को पूर्व एनडीए प्रशिक्षुओं के बीच सर्वोच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए एफओसी-इन-सी (दक्षिण) ट्रॉफी प्रदान की गई।

(घ) नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (विस्तारित) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सीएनएस स्वर्ण पदक और नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम (नियमित) में कमांडेंट, भारतीय नौसेना अकादमी रजत पदक क्रमशः कैडेट ऋषिकेश वी चैतन्य और कैडेट सात्विक दीक्षित को प्रदान किया गया।

(ई) महानिदेशक तटरक्षक ट्रॉफी कैडेट ईशान शेखर को प्रदान की गई।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रशिक्षुओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और अभ्यास के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण कर्मचारियों के समर्पण की सराहना की, साथ ही अभिभावकों के अटूट सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने विदेशी प्रशिक्षुओं को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग मजबूत हुआ है और वैश्विक स्तर पर भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण उत्कृष्टता उजागर हुई है।

परेड के समापन पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान, कमांडेंट, आईएनए और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं को पट्टियाँ प्रदान कीं। उन्होंने उन गौरवान्वित परिवारों से बातचीत की, जो कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था के सफल समापन का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे।

12वाँ चिंतन शिविर - 2025, धरमपुर का समापन समारोह

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का 'विकसित गुजरात@2047' के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को गति देने के लिए 'थिंकिंक वेल-डूइंग वेल' का भाव जगाने का आह्वान

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात समग्र देश के लिए विकास का रोल मॉडल बना, इसका श्रेय हमारे सामूहिक चिंतन तथा लोगों का भला करने की इच्छाशक्ति को जाता है
- अधिकारी ऑनरशिप के साथ पूर्ण समर्पण, दायित्व एवं लोक हित की प्रतिबद्धता से कार्यरत रहें
- केवल फाइल वर्क से संतोष न मानते हुए नियमित फील्ड विजिट तथा वास्तविक समस्याओं का सूझ-बूझ से सामना करने की पहल वृत्ति कार्यक्षमता को अनेक गुना बढ़ाएगी

मुख्यमंत्री का कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प

-: उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी :-

- चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन से सुदूरवर्ती मानव के कल्याण तथा राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने का मार्ग स्थापित करें
- चिंतन शिविर से कुछ नया सीखकर लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें

.....

गांधीनगर,29 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का आ'न किया है कि वे सभी 'विकसित गुजरात@2047' के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' के दो स्तंभों पर आधारित विकास यात्रा को और गति देने के लिए 'थिंकिंग वेल-डूइंग वेल' का भाव जगाएँ।

श्री पटेल ने वलसाड जिले में धरमपुर स्थित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' थीम के साथ आयोजित 12वें चिंतन शिविर का शनिवार को समापन कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के संकल्प में गुजरात को अग्रसर रखने का जो रोडमैप हमने लोगों के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' मंत्र के साथ तैयार किया है, उसे यह चिंतन शिविर 'थिंकिंग वेल-डूइंग वेल' के भाव से वैचारिक कलेवा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों से कहा कि वे कर्तव्यों तथा विभागों की जिम्मेदारी ऑनरशिप, पूर्ण समर्पण, दायित्व एवं लोक हित की प्रतिबद्धता के साथ निभाएँ। उन्होंने

कहा कि हम जहाँ हों, वहाँ अपना श्रेष्ठ कार्य निष्पादन देकर राज्य के विकास में आम आदमी के सुख-सुविधा के कार्यों में कार्यरत रहेंगे, तभी आत्मसंतोष मिलेगा।

उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि केवल फाइल वर्क करके संतोष न मानते हुए नियमित रूप से फील्ड विजिट, स्थल पर उपस्थिति, वास्तविक समस्याओं का सूझ-बूझ से सामना करने की पहल वृत्ति और लोक हित एवं कल्याण के लिए संवेदना जगाकर कार्यक्षमता में अनेक गुना वृद्धि हो सकती है और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन से विकास की सच्ची दिशा निर्धारित हो सकती है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू कराए गए चिंतन शिविर की उत्तरोत्तर सफलता में टीम गुजरात का परिश्रम और जन हित का सामूहिक चिंतन फलदायी रहा है। 2003 के प्रथम चिंतन शिविर में श्री मोदी ने प्रेरणा दी थी, 'हमारा दृष्टिकोण एकीकृत हो, गाँवों को गरीबी से बाहर निकालें और एक भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे न रहे। आज जब भारत 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर है, तब इस शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने में हम सबकी ओर से कुछ योगदान होना चाहिए। यह केवल राजनीतिक या ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मानवजाति के उत्थान का एक छोटा प्रयास है।'

इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'जो कहना, वह करना' का मंत्र अपनाया है और यह बात साकार करते हुए वे करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए हैं तथा भारत तीसरी बड़ी आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। गुजरात में हमने उनके दिशादर्शन में सर्वांगीण विकास की गति तेज बनाकर प्रतिव्यक्ति आय को पिछले ढाई दशक में 19823 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख 22 हजार रुपए तक पहुँचाया है।

श्री पटेल ने तीन दिवसीय चिंतन शिविर के विभिन्न चर्चा सत्रों में हुए सामूहिक विचार-मंथन से मिले सुझावों पर वास्तविक क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास के लिए टीम स्पिरिट के साथ कार्यरत होने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कुपोषण के विरुद्ध सामूहिक अभियान शुरू करने का संकल्प व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने चिंतन शिविर में समूह चचाओं में आए विषयों पर हुए कामकाज के समय-समय पर मूल्यांकन और आगामी चिंतन शिविर में नई ऊर्जा तथा अधिक ऊँचे विकास लक्ष्यों के साथ मिलने की अपेक्षा व्यक्त की।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने चिंतन शिविर के विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन से सुदूरवर्ती मानव के कल्याण तथा राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने का मार्ग स्थापित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि शिविर में हुई उदार मन से एवं पारदर्शी चचाएँ राज्य के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। यह जरूरी है कि तीन दिवसीय सामूहिक मनोमंथन से तैयार हुए मुद्दे केवल आर्काइव में ही न रहें, बल्कि उनका उचित डॉक्यमेंटेशन हो, जिसका सीधा लाभ गुजरात के आम नागरिकों को मिले।

श्री संघवी ने चिंतन शिविर से कुछ नया सीखकर लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि केवल सचिवालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि ठेठ जिला प्रशासन तक शिविर की फलश्रुति पहुँचाएँ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित हुआ चिंतन शिविर सभी नागरिकों के हित और किसी गरीब के आँसू पोंछने का संवेदनापूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने शिविर के आयोजन में सहयोग देने के लिए राजचंद्र मिशन का आभार व्यक्त किया।

तीन दिवसीय चिंतन शिविर के समापन अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, वरिष्ठ सचिव, जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग के सचिव श्री हारित शुक्ला ने इस शिविर की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

वैश्विक क्रेताओं, विशेषज्ञों और युवा प्रतिनिधियों के मेघालय में आमंत्रण के साथ शिलांग में चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम का उद्घाटन

(जीएनएस)।

एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठक, प्रथम पूर्वोत्तर भारत जैविक सप्ताह और चौथे आईएफओएएम विश्व जैविक युवा शिखर सम्मेलन (28 नवंबर- 1 दिसंबर 2025) के रूप में चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आज कोर्टयार्ड बाय मैरियट, शिलांग में औपचारिक उद्घाटन किया गया।

मेघालय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मेगनोलिया, एपीडा, आईएफओएएम-ऑर्गेनिक्स एशिया के सहयोग से तथा नेरामेक की सहायता से आयोजित इस कार्यक्रम में कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, आयातक, जैविक विशेषज्ञ और युवा प्रतिनिधिमंडल एक साथ एकत्रित हो रहे हैं।

उद्घाटन समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ पूर्वोत्तर परिषद के सचिव श्री सतिंदर कुमार भल्ला, मेघालय सरकार के आयुक्त एवं सचिव डॉ. विजय कुमार डी, एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव, मेघालय सरकार के मुख्य सचिव डॉ. शकील पी. अहमद, मेघालय सरकार की उप सचिव श्रीमती सलोनी

वर्मा, आईएफओएएम के सलाहकार ब्रेंडन होरे, आईएफओएएम एशिया की कार्यकारी निदेशक जेनिफर चांग, एनईआरएएमएसी के प्रबंध निदेशक श्री भास्कर बरुआ, एपीडा की महाप्रबंधक डॉ. सास्वती बोस, आईएफओएएम एशिया के अध्यक्ष मैथ्यू जॉन और क्रिसिल की एसोसिएट निदेशक श्रीमती प्रियंका उदय शामिल थे।

उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में, एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने पूर्वोत्तर भारत के जैविक उत्पादों की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत जैविक सम्मेलन के पहले संस्करण ने 22 देशों के हितधारकों को एक साथ एक मंच पर जोड़ा है, जो इस क्षेत्र की जैविक क्षमता में उनकी गहरी अंतरराष्ट्रीय रुचि दशार्ता है। हमने मेघालय के जैविक उत्पादों की वैश्विक पहचान को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, कृषि मंत्रालय, एनईसी और आईएफओएएम एशिया के साथ सहयोग किया है।

उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ते हुए, हमारा लक्ष्य इसे एक वार्षिक आयोजन बनाना है, जिसका आयोजन हर वर्ष विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किया जाएगा ताकि दुनिया भर में क्षेत्रीय जैविक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया जा सके। हम मेघालय के किसानों, एफपीओ और हितधारकों को आगामी बायोफैच में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जहां भारत एक भागीदार देश है, ताकि वे अपनी उपज को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर सकें।

इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के जैविक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार संबंधों को मजबूत करना, सतत और पुनयोर्जी कृषि को बढ़ावा देना एवं संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से युवा नेतृत्व को प्रोत्साहन देना है। बी2बी सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्षेत्रीय दौरों की योजना के साथ, यह आयोजन मेघालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैविक क्षमता को प्रदर्शित करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा।

पीएमएमएल शोधकताओं के लिए दुर्लभ अभिलेखीय संग्रह तक दूरस्थ पहुंच को संभव बनाता है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल), जो स्वतंत्रता के बाद से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, इसने अपने विशाल अभिलेखीय संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पीएमएमएल में दुर्लभ अभिलेखीय सामग्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 1,300 से ज्यादा व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित 2.5 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज शामिल हैं। आधुनिक और समकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाले प्रामाणिक शोधकर्ता और विद्वान नियमित रूप से इन अभिलेखों का अवलोकन करते हैं।

एक ऐतिहासिक पहल के तहत, पीएमएमएल अपने दुर्लभ अभिलेखीय संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत पत्र-पत्रिकाएँ, पत्राचार, भाषण, डायरियां और समाचार पत्र लेख शामिल हैं, का एक व्यापक डिजिटलीकरण परियोजना शुरू कर रहा है। यह परिवर्तनकारी प्रयास, वास्तविक शोधार्थियों के लिए सीमित दूरस्थ पहुंच को सक्षम करते हुए, नाजुक दस्तावेजों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है। अक्सर उपयोग की जाने वाली सामग्री का एक बड़ा हिस्सा पहले ही डिजिटलीकृत, अपलोड और नव-विकसित प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

इन डिजिटल अभिलेखागारों तक दूरस्थ पहुँच की सुविधा के लिए एक समर्पित सूचना प्रौद्योगिकी मंच बनाया गया है। पंजीकृत विद्वान अब विशिष्ट अभिलेखीय दस्तावेजों को देखने के लिए पीएमएमएल परिसर में आए बिना ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वीकृत होने के बाद, अनुरोधित सामग्री केवल देखने के लिए विद्वान के कंप्यूटर पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

पीएमएमएल के डिजिटल अभिलेखागार का शुभारंभ, अमूल्य ऐतिहासिक संसाधनों की सुरक्षा करने तथा विश्व भर के शोधकताओं, विद्वानों और ज्ञान चाहने वालों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पीएमएमएल के निदेशक श्री अश्विनी लोहानी ने कहा कि यह पहल उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और अभिलेखीय सामग्रियों तक आसान पहुंच बढ़ाकर आधुनिक और समकालीन भारत के अध्ययन को मजबूत करने के लिए संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रहीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रहीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

जीडीपी ग्रोथ रेट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और स्पष्टता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है

मुख्यमंत्री योगी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ लगातार सुधारों, स्थिर शासन और विकास-केंद्रित दृष्टिकोण की सफलता को दर्शाती है। नया भारत आत्मविश्वास के साथ, महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक विकास के स्पष्ट रोडमैप को लेकर आगे बढ़ रहा है।' अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

जीडीपी ग्रोथ रेट यह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को प्रगति करने से नहीं रोक सकती

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट यह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को प्रगति करने से नहीं रोक सकती। भारत सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है और दुनिया भी इस बात को मान रही है। भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

भारत ने जीडीपी में बड़ी छलांग लगाई है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संभव हुआ है

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत ने जीडीपी में बड़ी छलांग लगाई है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर सेक्टर में तेजी से काम हुआ है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक, भारत दुनिया के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहा है।

मझिगवांः मम्मृता ग्वास गली निर्माण में 2 किश्तें नगीपुर अखोला तहसील विकल, 20 मीटर तक काम शुरू न हुआ - ग्रामीणों की शिकायत, पीएम आवास योजना में देरी, तहसीलदार से मांग

(जीएनएस)।

पीलीभीत,29 नवंबर बीसलपुर तहसील के ग्राम मझिगवां में ढट आवास योजना के तहत मम्मृता ग्वास गली निर्माण का काम अटका पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप - 2 किश्तें जारी न होने से नगीपुर अखोला तहसील में 20 मीटर तक काम शुरू ही न हुआ। लाभार्थी परिवार परेशान, "घर तो बने, लेकिन गली न बनी तो पहुंच कैसे?"

समस्या का विवरणः

मझिगवां गांव में ग्वास कॉलोनी के पास गली निर्माण के लिए फंड आया, लेकिन किश्तें रुकने से ठेकेदार रुका। ग्रामीण बोले, "आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन बेसिक सुविधा जैसे गली न बने तो सब व्यर्थ।" तहसील स्तर पर विकल्प की कमी, अखोला क्षेत्र प्रभावित।

बीसलपुर तहसीलदार ने कहा, "शिकायत मिली, फंड रिलीज के लिए

ऊर को रिपोर्ट। जल्द समाधान।"

लेखपाल सुधीर की आत्महत्या पर वढ लेखपाल संघ का धरना

SIR दबाव व उत्पीड़न का आरोप - PCS अधिकारी संजय-शिवराज पर मुकदमा, 50 लाख मुआवजा, समय सीमा बढ़ाओ, SDM को ज्ञापन, बड़ा आंदोलन की धमकी

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 29 नवंबर कलीनगर तहसील परिसर में शुक्रवार सुबह 11 बजे वढ लेखपाल संघ ने फतेहपुर के लेखपाल सुधीर की आत्महत्या के विरोध में जोरदार धरना दिया। संघ ने रक्फ (विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण) कार्य के अत्यधिक दबाव को मौत का कारण बताया, उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक रक्फ पूरा करने की समयसीमा को अव्यवहारिक ठहराया - "दिन-रात मेहनत के बावजूद दबाव से टूट गए।"

धरने का पूरा विवरणः

तहसील परिसर में सैकड़ों लेखपाल जमा हुए, नारेबाजी की। तहसील अध्यक्ष वृंदावन ने बोला, "ढउर अधिकारी संजय कुमार सक्सेना व शिवराज ने अनावश्यक दबाव डाला, सुधीर को उकसाया। इनके खिलाफ IPC 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) में मुकदमा दर्ज

गजेंद्र यादव, राजेंद्र कुमार यादव, दीपक मौर्य, देवेश कुमार, विकास सिंह, पुष्पा यादव, विवेक राना, मालती वर्मा सहित कई। उन्होंने बैनर

फतेहपुर में सुधीर ने SIR दबाव से तंग आकर जहर खा लिया, पोस्टमॉर्टम से पुष्टि। पीलीभीत में 957 केंद्रों पर रक्फ तेज, लेकिन लेखपालों

हो।" अन्य मांगें: मृतक मां को 50 लाख सहायता, SIR में मानसिक-शारीरिक दबाव खत्म, 1 माह वेतन बराबर प्रोत्साहन, समयसीमा बढ़ाओ।

मुख्य प्रदर्शनकारीः

थामे सुधीर को श्रद्धांजलि दी, सरकार को चेताया - "मांगें न मानीं तो जिले भर में बड़ा आंदोलन।" कलीनगर रज्ट महिपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की अपील।

पृष्ठभूमि व प्रभाव

की शिकायत - कम समय, ज्यादा काम। DM ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, "दबाव कम, सहयोग बढ़ाएंगे।" धरने से SIR कार्य प्रभावित, लेकिन संघ का संकल्प पक्का।

यातायात प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के दृष्टिगत पहले से ही मॉक ड्रिल्स एवं पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण कराएं

(जीएनएस)।

सीमावर्ती जनपदों के स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित करते हुए डाइवर्जन प्लान शेयर करने का भी सुझाव जिससे कि पीक डेस पर प्रयागराज आने वाले हेवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके

बैठक में सर्वप्रथम इस वर्ष की यातायात प्रबंधन एवं कंटेंजेन्सी

योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों ने मेला अवधि में सीमावर्ती जनपदों से मेला क्षेत्र की ओर आने वाली भीड़ को आवश्यकतानुसार रोकने एवं डाइवर्ट करने हेतु बनाए गए डायवर्जन प्लान के बारे में अवगत कराया। सातों मुख्य मार्गों पर चिन्हित पार्किंग स्थलों की अपेक्षित क्षमता एवं उनमें की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में भी अवगत कराया गया जिसपर एडीजी यातायात महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि कौन सी कंटिंजेंसी प्लान कब लगाना है एवं उसकी चेन ऑफ कमांड क्या होगी उसके बारे में बैरिकेटिंग पर लगे पुलिसकर्मियों को भी जानकारी हो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने अंतर जनपदीय एवं अन्तर राज्यीय सीमाओं पर कौन सा डायवर्जन प्लान कब लगाने की आवश्यकता है उसका निर्णय सभी जनपदीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए एडीजी जोन को लेने की जिम्मेदारी दी है। यातायात प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के दृष्टिगत उन्होंने पहले से ही मॉक ड्रिल्स एवं पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण करा लेने के भी निर्देश दिए।

एडीजी जोन प्रयागराज ने ई रिक्शा के मूवमेंट प्लान, 2 व्हीलर्स के रूट प्लान तथा पार्किंग स्थलों की कैपेसिटी का सही आकंलन करते वहां अपेक्षित व्यवस्थाएं स समय करने के निर्देश देते हुए पार्किंग स्थलों को सब सेक्टरों में भी विभाजित करने को कहा जिससे कि उसके क्षेत्रफल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके एवं श्रद्धालुओं को गाड़ी पार्क करने एवं निकालने में भी आसानी हो। आइसीसीसी से निगरानी करने वाले अधिकारियों की सूची बनाकर उनकी भी चेन ऑफ कमांड तय करने के निर्देश दिए गए।

इस वर्ष मकर संक्रांति (15 जनवरी) एवं मौनी अमावस्या (18 जनवरी) के बीच सिर्फ 3 दिनों का गैप है इस कारण मकर संक्रांति को आने वाली भीड़ मौनी अमावस्या तक रुक सकती है। श्रद्धालु 7 मार्गों से प्रयागराज आते हैं जिसमें जौनपुर, वाराणसी, रीवा, मिजार्पुर, कानपुर, लखनऊ एवं अयोध्या मुख्य हैं। इस बार स्नानार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी घाटों पर नम्बरिंग करते हुए उनके मैप को गूगल से इंटीग्रेट कराने पर भी सहमति बनी है जिसके लिए मेला प्रशासन अब गूगल के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही स्नानघाटों एवं अन्य मुख्य स्थलों के चिन्हांकन हेतु गुब्बारों का भी प्रयोग किया जाएगा।

बैठक में आइजी श्री अजय कुमार मिश्रा, पुलिस आयुक्त श्री जोगेंद्र कुमार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस डॉ अजय पाल, मेला अधिकारी श्री ऋषिराज, नगरायुक्त श्री सीलम साई तेजा, अपर मेला अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद समेत सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मोहनपुर गोविंदपुर डॉ. अंबेडकर सामुदायिक केंद्र(बारात घर)की जर्जर हालत, गेट टूटा पड़ा

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 29 नवंबर सेहरामऊ थाना उत्तरी क्षेत्र के मोहनपुर गोविंदपुर में डॉ. अंबेडकर सामुदायिक केंद्र (बारात घर) की हालत दयनीय हो गई है। गेट काफी समय से टूटा पड़ा, न सफाई होती, न रखरखाव - जर्जर इमारत से ग्रामीण परेशान। सामुदायिक केंद्र होने के बावजूद उपेक्षा, बारात व कार्यक्रमों में दिक्कत।

समस्या का विवरणः

ग्रामीण बोले, "गेट टूटा तो चोर-उचक्के घुसते, सफाई न हो तो गंदगी फैली। अंबेडकर जी का नाम जुड़ा, लेकिन जिम्मेदार सोए।" केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही - बजट न आने या अधिकारी नजरअंदाज। इलाके में कई

शिकायतें, लेकिन कार्रवाई शून्य।

थानाध्यक्ष ने कहा, "शिकायत मिली, तहसील को सूचना - जल्द मरम्मत।"

'पटाखा बुलेट' के धमाकों से कोतवाली गेट पर हड़बड़ी, युवक फरार तो पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

अवैध साइलेंसर सीज, 16,500 चालान, रढ अभियान में सख्ती, ध्वनि प्रदूषण व खतरे पर लगाम

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 29 नवंबर पूरनपुर कोतवाली गेट पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे एक युवक ने अपनी मॉडिफाइड 'पटाखा बुलेट' मोटरसाइकिल से लगातार तेज धमाके मचाकर सबको दहला दिया। कोतवाली परिसर और आसपास के लोग घबरा गए, मानो असल पटाखे फूट रहे हों। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यातायात नियम तोड़कर युवक मौके से फरार हो गया, लेकिन क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार की तत्परता ने कुछ ही दूरी पर उसे और बुलेट को पकड़ लिया।

घटना का पूरा ब्योराः

सुबह के व्यस्त समय में युवक ने संशोधित बुलेट से पटाखा जैसे धमाके किए, जो अवैध 'पटाखा साइलेंसर' की वजह से हुए। यह साइलेंसर न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, बल्कि सड़क पर खतरा भी बढ़ाता है - वाहन की गति अनियंत्रित हो जाती है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "धमाकों से लगा जैसे बम फटा, बच्चे डर गए।" युवक ने पुलिस को चुनौती देते हुए

नियम उल्लंघन किया, लेकिन सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अशोक ने पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही किलोमीटर दूर युवक पकड़ा गया। जांच में साइलेंसर अवैध पाया गया, जो शहर में तेजी से फैल रहा चलन है।

पुलिस ने फौरन बुलेट को सीज कर लिया और यातायात नियम उल्लंघन व अवैध संशोधन के लिए युवक पर भारी 16,500 रुपये का चालान ठोंका। इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा, "नगर में पटाखा बुलेट का ट्रेंड बढ़ रहा, जो पर्यावरण व सुरक्षा के लिए घातक। रढ अभिषेक यादव के आदेश पर विशेष अभियान चल रहा - कोई छूट नहीं मिलेगी।" उन्होंने चेतावनी दी कि गैरकानूनी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी, साइलेंसर रोड रोलर से कुचले जाएंगे।

प्रभाव व अभियानः

इस कार्रवाई से पूरनपुर के युवाओं में हड़कंप मच गया। कई बुलेट चालक अब साइलेंसर हटाने की सोच रहे। रढ ने जिले भर में अभियान तेज करने के निर्देश दिए - ट्रैफिक पुलिस गश्त बढ़ाएगी, चेकिंग पॉइंट्स लगेंगे। विशेषज्ञ बोले, "ऐसे संशोधन न सिर्फ कानून तोड़ते, बल्कि दुर्घटनाओं को न्योता देते।" इलाके में राहत की लहर, सड़कें शांत।

सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में जानलेवा हमला, युवक की एक आंख की रोशनी गई, 8 दिन बाद भी मुकदमा नहीं

(जीएनएस)।

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में युवक बब्लू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। यूसुफ नगर, बगियामऊ निवासी पीड़िता प्रीति यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि 21 नवंबर की शाम लगभग 7:30 से 9 बजे के बीच दबंगों ने शराब के पैसे न देने पर उनके पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता के अनुसार कल्लू यादव उर्फ अंकुर पुत्र बाबूलाल निवासी बगियामऊ अपने साथियों के साथ अचानक विवाद पर उतर आया और देखते ही देखते सभी ने मिलकर बब्लू यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी सूचना पर मौके पर पहुँची प्रीति यादव ने अपने पति को खून से लथपथ और अचेत अवस्था में पाया। पहले गैलेक्सी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें मेडिकल कॉलेज

रेफर कर दिया गया। वर्तमान में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हमले में बब्लू यादव की बाईं आंख में गंभीर चोट आई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंख की रोशनी आजीवन जा चुकी है। पीड़िता ने बताया कि पति की दृष्टि बाधित हो जाने से उनका हँसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया है। आरोप है कि सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने घटना के 8 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके चलते वह डीसीपी से लेकर थाने तक लगातार चक्कर काट रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है वहीं उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

घर में घुसकर महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

1 साल से छेड़छाड़ का सिलसिला - आरोपी राजेश फरार, पति बाहर होने का फायदा उठाया, परिवार की चीखें सुन भागा, पुलिस ने कढउ 354, 452, 307 के तहत केस दर्ज कर तलाश तेज

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 29 नवंबर न्यूरिया थाना क्षेत्र के एक शांत ग्रामीण इलाके में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने एक बार फिर सिर चढ़कर बोल दिया है। यहां 20 नवंबर की काली रात करीब 11 बजे एक महिला के घर में घुसकर आरोपी राजेश कुमार (पुत्र श्यामलाल, उसी गांव का निवासी) ने ऐसी हैवानियत दिखाई, जो रोंगटे खड़े कर देगी। पिछले लगभग एक साल से पीड़िता को परेशान कर रहा यह आरोपी, रास्तों में रोककर छेड़छाड़ करता था। लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी - कुल्हाड़ी थामकर घर में घुसा, अश्लील हरकतें कीं, और विरोध पर सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना का पूरा विवरणः

पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका पति मजदूरी के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहता है।

इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए राजेश ने रात के अंधेरे में कुल्हाड़ी लहराते हुए घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस आया। अचानक हमले से स्तब्ध महिला ने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने गुस्से में कुल्हाड़ी से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। खून से लथपथ होकर वह जमीं पर गिर पड़ी। दर्द से चीखने-चिल्लाने की आवाज घर में सोए परिवार के अन्य सदस्यों को जगा दिया। जैसे ही परिजन दौड़े, आरोपी ने पीड़िता को "मार डालूंगा" की धमकी देकर मौके से भाग निकला।

घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने सिर की चोटों को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पीड़िता ने पुलिस पूछताछ में कहा, "वह 1 साल से मेरा पीछा कर रहा था। रास्ता रोकता, गालियां देता। लेकिन सोचा नहीं था कि घर में घुसकर इतना बड़ा कदम उठाएगा।" परिवार वाले भी सदमे में हैं - वे बताते हैं कि आरोपी का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था, लेकिन डर के मारे चुप थे।

पुलिस कार्रवाईः

न्यूरिया थाना प्रभारी सुभाष मावी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें शामिल हैं - कढउ की धारा 354 (महिला से छेड़छाड़), 452 (घर में घुसकर आपराधिक आशय), और 307 (हत्या का प्रयास)। थानाध्यक्ष ने कहा, "हमारी टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। उसके फरार होने की सूचना पूरे जिले में फैला दी गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर न्याय दिलाएंगे।" पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, साक्ष्य जुटाए, और परिजनों से गहन पूछताछ की। साथ ही, इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

सामाजिक संदेशः

यह घटना पीलीभीत के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की असुरक्षा को उजागर करती है। रढ अभिषेक यादव ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में तत्काल शिकायत और सख्त कानूनी कार्रवाई ही समाधान है। पीड़िता का परिवार अब न्याय की उम्मीद में है, लेकिन डर का साया अभी भी बना हुआ है।

बुधेश्वर में हादसाः पतंग के मांझे में फँसी स्कूटी सवार लड़की, गंभीर रूप से घायल

(जीएनएस)।

लखनऊ। पारा थाना क्षेत्र के बुधेश्वर इलाके में एक गंभीर हादसा हुआ, जब सड़क से गुजर रही एक लड़की की गर्दन अचानक हवा में लटक रहे पतंग के मांझे में फँस गई। लड़की इसे समय रहते नहीं देख पाई। मांझा लगते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अपनी स्कूटी सहित सड़क पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और घायल लड़की को नजदीकी अस्पताल भेजा गया यह घटना इस बात की गंभीर चेतावनी है कि पतंग उड़ाने के दौरान उपयोग किए जाने वाले कांच या मांसल तार वाले मांझे केवल खेल का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकते हैं। वाहन चालकों और राहगीरों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे खतरनाक मांझों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पतंगबाजी के दौरान अक्सर मांझे सड़क या गलियों तक लटक आते हैं, जिससे आम लोगों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। यह हादसा यह दशार्ता है कि मनोरंजन

और उत्सव के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ऐसे मांझों पर प्रतिबंध है, फिर भी उनकी बिक्री और उपयोग जारी है। सामान्य जनता से अपील है कि वे पतंग उड़ाने के लिए खुले मैदानों का उपयोग करें, बच्चों की निगरानी रखें और खतरनाक मांझों की सूचना स्थानीय प्रशासन को तुरंत दें। सरकार को इन मांझों की बिक्री पर सख्ती करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। विशेष रूप से चाइनीस मांझा की रोकथाम और जांच-निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह आम जनता के लिए अत्यंत खतरनाक साबित हो रहा है।